Modernisation and Expansion of Postal Network in Orissa

3724. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any step in the direction of modernisation and expansion of postal network in Orissa in 8th Five Year Plan period;

(b)rif so, the details thereof?

(c) the funds earmarked for the expansion and modernisation of postal netilvoirk in 9th Five Year Plan period in Orissa; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir.

(b) The steps taken in the direction pf modernisation and expansion of the postal network in Orissa in the 8th Five Year Plan period are as below:

1. Opening of 94 Extra Departmental Post Offices.

2. Opening of 12 Departmental Sub Post Offices.

3. Opening of 35 Panchayat San-char Sewa Kendras.

4. Installation of 98 Multi Purpose Counter Machines.

5. Installation of 2 Local Area networks for Savings Bank work.

6. Savings Bank Control Organisation computerisation in 18 Head Post Offices.

7. Modernisation of 2 post offices.

S. Installation of 3 very Small Aperture Terminals.

9. Setting up of 14 Extended Satellite Money Order centres.

10. Computerisation of 1 mail office.

11. Modernisation of 2 mail offices.

12. Computerisation of Postal Life Insurance work in Orissa Postal Circle.

(c) and (d) The outlay for the draft 9th Plan Department of Posts which is yet to be finally approved is Rs. 550 crores. This includes a provision of Rs. 414.94 crore for expansion of postal network and modernisation in the country. State wise or Postal Circle wise outlays have not been proposed in the 9th Plan. Postal Circle wise provision of funds is made when Annual Plans are implemented. During 1997-98, the Orissa Postal Circle for expansion of the postal network and modernisation.

Waitlisted Persons under Non-OYT in Patiala District of Punjab

3725. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of persons on the waiting list in the Patiala district of Punjab under non-OYT scheme as on 31st March, 1998; and

(b) whether the existing capacity of telephone exchanges in the district is being augmented to meet the demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) As on 31.3.98 the number of persons on the waiting list under the Non-OYT General category was 15873 and Non-OYT Special category was 13.

(b) Yes, Sir. Expansion of 20,400 lines of switching capacity has been planned during 1998-99 to clear the existing waiting list.

Andhra Pradesh Government's Request to bring Down Telecom Tariff

3726. DR. Y. LAKSHMl PRASAD: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether State Government of Andhra Pradesh has requested to being

down telecom tariff ensuring minimum cost of communications; and

(b) if so, the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) There is no such proposal at present.

(b) Does not arise in view of (a) above.

डाक व तारघरों की आवश्यकता

3727. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्धारित मानदंडों के अनुसार भारत में कितने डाक व तारघरों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में विभिन्न राज्यों में कार्यरत डाक व तारघरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डाक व तार घरों का आज भी अत्यधिक अभाव है तथा वे राष्ट्र की मुख्य धारा की तुलना में पिछड़ रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को कम करने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) क्या गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में डाक व तार घरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) दूरी और जनसंख्या के दो मानदंडों के आधार पर जिन गांवों में डाकघर खोलने का औचित्य बनता है, उनकी संख्या लगभग 6000 है। आय संबंधी तीसरे मानदंड की जांच तब की जाती है जब एक ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाता है। कार्य कर रहे डोकघरों का सर्किलवार ब्यौरा विवरण-। में दिया गया है (नीचे दिखिये)।

इस समय विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे तारघरों की संख्या का ब्यौरा विवरण-॥ में दिया गया है। (नीचे देखिये)।

(ख) से (घ) जब डाकघर खोलने संबंधी लक्ष्य नियत किए जाते हैं, तब ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों पर यथोचित विचार किया जाता है। जनजातीय, पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंडों को और अधिक शिथिल किया गया है। वार्षिक योजना 1998-99 के दौरान देश भर में 648 डाकघर खोलने का लक्ष्य है और ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, 598 अतिरिक्त विभागयि शाखा डाकघर खोले जायेंगे। उक्त अवधि के दौरान खोले गए कुछ विभागीय शाखा डाकघर खोले जायेंगे। उक्त अवधि के दौरान खोले गए कुछ विभागीय उपडाकघर भी ग्रामीण क्षेत्र में ही आते हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में डाकघर खोलने संबंधी लक्ष्य इस प्रकार है:—

गुराजत	उड़ीसा	मध्य प्रदेश
42	12	52

तारघर खोलना परियात पर निर्भर करता है। यदि परियात की न्यूनतम संख्या उपलब्ध है तो इसकी योजना बनाई जाती है।

विवरण-।

डाकघरों का सर्किलवार और श्रेणीवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/ संघशासित क्षेत्र का नाम	प्रधान डाकघर (एचओ)	विभागीय उपडाकघर (डीएसओ)	अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर (ईडीएसओ)	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ)	कुल
1.	आध्र प्रदेश	104	2358	53	13657	16172
2.	असम	16	584	36	3182	3818
3.	बिहार	42	1436	127	10200	11805
4.	दिल्ली	9	413	21	113	556
5.	गुजरात	42	1373	46	7501	8962
6.	हरियाणा	15	459	14	2115	2603